RJPP Vol. XVII No.1 2019 ISSN (P): 0976-3635 (e):2454-3411 Impact Factor 6.76 (SJIF)

भारत में बढ़ता हुआ नक्सलवाद

डॉ॰ मनोरमा राय
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
धर्मेन्द्र सिंह मैमोरियल कॉलिज, अटौला,मेरठ
Email: dsmcollegeatola@gmail.com

सारांश–

नक्सलवाद वर्तमान भारत की एक ज्वलंत समस्या है नक्सलवाद से समूचा देश ग्रसित है यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल राष्ट्रीय एकीकरण की दशा और दिशा को भंगित कर रही है बल्कि देश की सम्प्रभुता, सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रही है। नक्लवाद का प्रादुर्भाव पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिले में नक्सलवाडी गाँव की धरती पर किसान आन्तदोलन के रूप में सन् 1967 में हुआ और फिर यहाँ से भारत के प्रायः सभी भागों में फैल गया। अधिकांश नक्सलवादी हीन भावना से ग्रसित होते हैं तथा अपने जीवन से पूरी तरह निराश एवं स्वप्नहीन व्यक्ति होते हैं उनके समस्त कार्य प्रतिशोध की भावना पर आधारित होते हैं तथा हिंसक कार्यों से भरे पडे होते हैं इनके शोषण एवं अत्याचारों से उच्च जातियों में तीव्र असंतोष और अशान्ति की रचना हुई है। अपने हक को पाने के लिए चलाया गया आन्दोलन नक्सलवाद अब उग्रवाद के रूप में देश के सामने एक अत्यन्त विकट समस्या है, जिसके निराकरण हेतु बहुकोणीय प्रयास की आवश्यकता है।

प्रमुख शब्द–*नक्सलवाद, ज्वलंत, स्वप्नहीन, कम्यूनिष्ठ, सम्प्रभुता, प्रादुर्भाव, बहुकोणीय।*

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 15.02.2019
Approved: 28.02.2019

डॉ॰ मनोरमा राय

भारत में बढ़ता हुआ नक्सलवाद

RJPP 2019,
Vol. XVII, No. 1,
pp. 73-83
Article No.10

Online available at :
https://anubooks.com/?page_id=5286

डॉ० मनोरमा राय

प्रस्तावना

नक्सलवाद वर्तमान भारत की एक ज्वलंत समस्या है नक्सलवाद से समूचा देश ग्रसित है यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल राष्ट्रीय एकीकरण की दशा और दिशा को भंगित कर रही है बल्कि देश की सम्प्रभुता, सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रही है। नक्लवाद का प्रादुर्भाव पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिले में नक्सलवाडी गाँव की धरती पर किसान आन्तदोलन के रूप में सन् 1967 में हुआ और फिर यहाँ से भारत के प्रायः सभी भागों में फैल गया। वर्तमान में नक्सलियों का प्रभाव पशुपति (नेपाल) से लेकर तिरूपति (आन्ध्र प्रदेश) तक हो चुका है। धनबल में भी वे काफी मजबूत हो चुके हैं। दे के लगभग 40 प्रतिशत भू–भाग (20 राज्यों के 223 जिलों) पर उनका समानान्तर राज चलता है। एक अनुमान के अनुसार अकेले छत्तीसगढ़ में 20 हजार सशस्त्र नक्सली हैं। देशभर में इनकी संख्या एक से डेढ़ लाख मानी जाती है। इनका सालाना टर्न ओवर 1500 करोड़ रुपये से अधिक का है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक उडीसा, हरियाणा तथा अन्य राज्य जो नक्सली आतंकवाद के ताप से बेहद पीडित है। इन राज्यों में नक्सली हिंसा बढ़ती जा रही है नक्सलवादी आन्दोलन का प्रभव क्षेत्र देश के कई सीमाई राज्यों में चल रहे उग्रवादी, अलगाववादी आन्दोलनों की तुलना में काफी फैल चुकी है। सरकारी आंकड़ों को देखने से हमें अभिज्ञात होता है कि जम्मू कश्मीर और उत्तरपूर्वी राज्यों के सभी उग्रवादी आन्दोलनों को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो उनका प्रभाव क्षेत्र देश का कुल 11.09 प्रतिशत क्षेत्र और 4.15 प्रतिशत जनसंख्या ही आती है जबकि नक्सली प्रभावी क्षेत्र में देश का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र और 35 प्रतिशत जनसंख्या आ चुकी है जिन क्षेत्रों में नक्सलियों की बहुलता है वहां उनका समानान्तर प्रशासन चलता है।

आज यह आन्दोलन 14 राज्यों के 165 जिलों को प्रभावित कर रहा है। नक्सलवाद से समूचा देश ग्रसित है आये दिन आगजनी लूट और हत्या की घटनाएं समाचार पत्रों की मुख्य खबरें बन रही है नक्सलवादी आन्दोलन के तीन घोषित उद्देश्य थे–

1. खेत जोतने वाले को खेत पर हक मिले।
2. विदेशी पूँजी की ताकत सीमित की जाये।
3. वर्ग और जाति के विरूद्ध संघर्ष हो।

भारत में नक्सलवादी समस्या अत्यधिक विकराल एवं व्यापक रूप धारण करती जा रही है यह समाज तथा राष्ट के लिए संकट का बाह्य है तो राष्ट्र के नागरिकों के लिए प्राणों का ग्राहक न जाने कब, कहां और किसे इस सर्पदंश का सामना करना होगा यह आन्दोलन क्रूर है, धमकी नहीं देता है बल्कि रक्तपात और विध्वंस में विश्वास करता है।

जिन सामाजिक, आर्थिक स्थिति ने माओवादी आन्दोलन को जिस रूप में 1980 के दषक के दौरान आन्ध्रप्रदेश में क्रान्तिकारी राजनीति के लिए पूर्ण प्लेटफार्म प्रदान किया, उन्हीं परिस्थितियों से अन्य राज्यों जैसे बिहार, झारखण्ड, तथा छत्तीसगढ़ आदि के लिए भी उत्तरदायी

माना जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश में गतिशील सैन्यदल के रूप में पीपुल्स विबरेशन गुरिल्ला आर्मी के काले कारनामे गतिशील सैन्यदल के सर्वोत्तम उदाहरण है जिसने कुछ क्षेत्रों में समानान्तर सरकार बनाया। गुरिल्ला स्ट्रेटजी के आधार पर पूरे प्रदेश में शोषण, अत्याचार और अन्याय से बचने के लिए माओवादियों ने सरकार के विरूद्ध बहिष्कार की नीति को और भी अधिक मजबूत बना दिया।

प्राकल्पनाएं

नक्सलवाद क्या है? किसे कहते हैं? इसकी परिभाशाएं क्या हैं? नक्सलवाद एक ऐसी विधा है जिसके आधार पर एक संगति समूह या दल अपने स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित हिंसा का प्रयोग करता है। मष्त्यु या संहार नक्सलवाद के क्रियात्मक कार्यक्रम का अविभाज्य अंग है। नक्सलवादियों की मान्यता है कि समाज में आवश्यक एवं मनोवांछित परिवर्तन शान्तिपूर्ण राजनैतिक सामाजिक प्रक्रियाओं से नहीं लाया जा सकता, क्योंकि निहित स्वार्थ सत्ताधारियों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है और कृषि अर्थव्यवस्था पर सामन्ती शासन करता है। ऐसी स्थिति में शस्त्र संघर्ष गुरिल्ला युद्ध ही एकमात्र उपाय है।

नक्सलवाद के विविध रूप है इसका कोई निष्चित स्वरूप नहीं है। नक्सलवादी बहुरूपियों की भांति नानास्वरूप धारण कर अपने शत्रुओं को क्षतिग्रस्त व आतंकित करते हैं अपने बहुरूपियेण के कारण ही नक्सलवाद स्वयं को सामान्य लोगों के आक्रोश से बचाता रहा है इस संदर्भ में हमारी शोध प्राककल्पना है कि नक्सलियों की वैचारिक अवधारणा उनके समूहों की सशक्तिशीलता के रूप में उनकी मूल्य व्यवस्था और साथ ही वर्ग व्यवस्था का निर्देशन है, जबकि शून्य प्राककल्पना यह है कि नक्सलवादी साहित्यिक वैचारिकी एवं अस्तित्वात्मक वैचारिकी में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। ये दोनों ही प्राक्कलपना भावी अनुसंधान हेतु परीक्षणीय वक्तव्य है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में उद्देश्य यह है कि हमारे देश में आन्तरिक कलह बडे स्तर पर व्याप्त है, अतः आज तेजी से पांव पसार रहे और देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके नक्सलवादी आन्दोलन से युद्ध स्तर पर निपटने की आवश्यकता है नक्लवाद रूपी समस्या को केवल कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उडीसा, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ और पश्चिम बंगाल में व्याप्त उग्रवाद को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आखिर पंजाब हरियाणा, हिमांचल प्रदेश केरल और राजस्थान जैसे राज्यों में इस प्रकार की समस्या क्यों व्याप्त नहीं है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों की अध्यक्षता वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस विषय पर एक व्यापक शोध किया जाना चाहिए कि भारत में कुछ निश्चित वर्ग विशेषकर जनजाति समूहों और अन्य निर्धन समूहों से जुडे लोग, क्यों अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं? आखिर कोई भी व्यक्ति बिना किसी बडे कारण के हिंसा और मृत्यु का चयन नहीं करता। हमारा उद्देश्य इन कारणों का पता लगाना है।

नक्सलवादी आन्दोलनों का मुख्य आधारा निम्नजाति एवं उच्च जाति, अभिजात एवं अनाभिजात, उच्च भूमिपतियों एवं भूमिहीनों के बीच बडी विद्वेश व वर्ग संघर्ष है। लूट–मार, हत्या, धन तथा भू–सम्पत्ति पर जबरन कब्जा द्वारा राज्य में अस्थिरता पैदा करना नक्सलवादियों का महान धर्म है। यही कारण है कि पष्चिम बंगाल, बिहार, एवं झारखण्ड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाकर बकायदा नक्सलियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण ग्रहण कर ये नक्सली गिरोह के सदस्य पूर्वलक्षित क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुनः उन्हीं शिविरों में लौट जाते हैं।

नक्सलियों का व्यक्तित्व बनावट

अधिकांश नक्सलवादी हीन भावना से ग्रसित होते हैं तथा अपने जीवन से पूरी तरह निराश एवं स्वप्नहीन व्यक्ति होते हैं उनके समस्त कार्य प्रतिशोध की भावना पर आधारित होते हैं तथा हिंसक कार्यों से भरे पडे होते हैं इनके शोषण एवं अत्याचारों से उच्च जातियों में तीव्र असंतोष और अशान्ति की रचना हुई है। उनमें बदला लेने की क्रान्ति फूट पडी है। बिहार में 'रणवीर सेना' का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ है यह बिहार के बडे भू–स्वामियो का संगठन है जो अपनी भू–सम्पदा की रक्षा के लिए अपनी खोयी हुई भू–सम्पत्ति के लिए मैदान में हथियार लेकर उतर आये हैं। 'रणवीर सेना' सवर्ण समृद्ध जातियों के धड से वीर–बाह की तरह निकला है यह स्वर्ण समृद्ध जाति की रक्षा की भुजा थी। आज भी स्वर्ण जाति और नक्सलवादी गिरोह परस्पर लडते हैं। पूरा देश नक्सलवाद की बर्बरता से कपकपा उठा है इन नक्सलियों द्वारा अगणित नरमेघ हो चुके हैं। लाखों निरपराध स्त्रियों, पुरूषों, और बच्चों पर पाशविक अत्याचार किये गये हैं इनके द्वारा। यहाँ तक कि स्त्रियों की अस्मिता से खेलना इनका पेशा बन गया है पाशविकता का एंसा नग्न नृत्य करते हुए पाये गये हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लाखों व्यक्तियों के सम्पत्तियों को लूटकर उन्हें भिखारी बना दिया है इनकी रक्तपात की प्यास हजारों लाखें नरों के रक्त पी कर भी नहीं बुझती।

नक्सलवादी बहुधा उग्रवादी होते हैं

नक्सली स्वभाव से ज्यादातर उग्रवादी होते हैं और माओवादी के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। इनकी मान्यता है कि "यदि क्रन्ति उत्पन्न करना है तो क्रान्तिकारी दल का होना आवश्यक है।" उन्होंने 22 अप्रैल 1969 को 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया' क्रान्तिकारी दल का बीज रोपड किया। यह उद्‌घोषणा की गयी कि "हमारे दल का स्र्वप्रथम तथा प्रधान कार्य कृशक–जनों को मजदूरी के लिए पूरे देश में गुरिल्ला युद्ध का शंखनाद कर उत्तेजित करना, भू–सम्पदा विषयक खुली क्रान्ति का आह्वान करना ग्रामीण आधार का निर्माण करना, नगरों की घेराबन्दी के लिए देहात का प्रयोग करना और अन्ततः नगरों पर अधिकार करना तथा सम्पूर्ण देश को विमुक्त करना है।"

नक्सलवाद की पृष्ठभूमि

नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के टूटे हुए घटकों की सोच है जो क्रान्तिकारी चिन्तन से सम्बन्धित है। नक्सलवाद की उपरोक्त व्याख्या इनके

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर इंगित कर रहा है जिसका वर्णन समयचीन प्रतीत होता है।

जुलाई 1948 में आन्ध्रप्रदेश के तेलंगाना के 2500 गांवों के ग्रामीणों ने कृषक आन्दोलन के सदस्य के रूप में संगठित हुए थे, जिसे तेलगांना संघर्ष के नाम से जाना गया। आन्ध्र थिसीस में मांग किया गया कि भारतीय क्रान्ति को चीन के जनयुद्ध के विस्तारित पथ का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में जून 1948 में 'आन्ध्र पत्र' के नाम से वामपंथी विचारधारा के इक्यूमेंट प्रकाशित हुआ था जो माओत्सेतुंग के नवीन प्रजातांत्रिक विचारधारा पर आधारित था।

1964 में सी0पी0एम0, यूनाईटेड सी0पी0आई0 से टूटकर अलग हुआ था और वे चुनावों में भाग लेने के लिए सशस्त्र संघर्ष का परित्याग करने का निर्णय लिया जबकि देश में क्रान्तिकारी परिस्थितियां विधमान थी।

1965–66 के प्रमुख वामपंथी नेता चारू मजुमदान ने मार्क्स–लेनिन, आओत्सेतुंग के विचारों पर अधारित Histaric Eight Decuments की रचना की जो बाद में नक्सलवाद आन्दोलन का आधार बनी 1967 में सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में आम चुनाव में भाग लिया और बंगाल कांग्रेस के साथ मिलकर United Froun Government बनाया इससे पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में फूट हुआ और चारू मजुमदार जैसे नेता ने सीपीएम को क्रान्ति में धोखा देने वाले का नाम दिया।

25 मई 1967 सीपीएम के विद्रोही कार्यकर्ताओं जिनमें चारू मजूमदान एवं कानू सान्याल मुख्य थे के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाडी अनुमंडल के छोटे से गांव विद्रोही विपक्ष के रूप में क्रान्तिकारी कृषकों का एक संगठन तैयार संघर्ष किया, जिसका मुख्य उद्देश्य बैनामी जमीन को भूमिहीनों के बीच में वितरण करना था, कारण 02 मार्च 1967 को उस गांव के एक आदिवासी युवक स्थान को स्थानीय जमींदारों के गुण्डो के द्वारा पिटाई की गयी थी जिसके फलस्वरूप आदिवासियों में विद्रोह की भावना भडकी थी और वे शक्ति बल से अपनी जमीन जिन पर जमीदारों का कब्जा था, को मुक्त कराया था। सीपीएम के United Front Government द्वारा 03 मार्च 1967 से 24 मई 1967 तक कुल 72 दिनों के बीच उक्त संघर्ष को दबाने की भरसक कोशिश की गयी थी, जिसमें एक पुलिस सब इंसपेक्टर सहित नौ आदिवासी मारे गये थे केन्द्र में उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी जसने उक्त दमन को सही ठहराया था। यह विद्रोह पूरे भारत में ध्वनित हुआ था जिससे नक्सलवाद का जन्म हुआ। चूंकि यह घटना नक्सलवाडी जैसे गांव में घटित हुआ था इसीलिए इसका नाम नक्सलवाद पड़ा।

नक्सलविचारधारा का आयाम बढा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर बिहार, एवं आंध्रप्रदेश के सीबी0आई ने इस संघर्ष में योदान दिया। तमिलनाडु, केरल, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उडीसा एवं पष्चिम बंगाल के वामपंथी दल के सदस्यों ने All India Co-ordination commitie of Revolutionaries (AICCR) का गठन किया 14 मई 1968 को AICCR का पुर्ननामांकरण All India Co-Ordination Committee of Communist Revoluticnaries (AICR) के रूप में किया गया जिसने चुनावों के बहिष्कार का निर्णय लिया।

AICCCR के अनुसार फरवरी 1969 के नियर्णयानुसार 22 अप्रैल 1969 को सीपीआई (एमएल) नामक एक नई पार्टी का जन्म लेनिन के वार्षिक जन्मोत्सव के अवसर पर हुआ जिसके

केन्द्रिय संगठन समिति के सचिव चारू मजुमदार को बनाया गया।

01 मई 1969 जब कामरेड कानू सान्याल द्वारा सीपीआई एमएल के गठन की बात कही गयी तब सीपीआई एमएल एस एवं सीपीआई (एमएल) के समर्थकों के बीच तत्कालीन कलकत्ता के रशिद मिनार ग्राउंड में खूनी संघर्ष हुआ।

20 अक्टूबर 1969 को Maoist Communist Centre (MCC) का जम्न कन्हाई चटर्जी के नेतृत्व में हुआ जिसमें नकसलवादी संघर्ष का समर्थन तो किया परन्तु सोच की भिन्नता के कारण सीपीआई (एमएल) से अपनों को अलग रखने का निर्णय लिया क्योंकि सीपीआई (एमएल) के गठन के तरीके से वे सहमत नहीं थे।

भारत में दो प्रमुख वामपंथी नक्सलवादी या उग्रवादी समूह क्रियाशील हैं।

1. Maoist Communist Centre (MCC)
2. Peoples Wair Group (PWG)

एमसीसी के गठन के वर्ष विषय में दो राय देखने को मिल रहे हैं प्रायः मत के अनुसार कन्हाई चटर्जी के नेतृत्व में 20 अक्टूबर 1969 में एमसीसी वामपंथी संगठन का जनम हुआ जबकि दूसरे मत के अनुसार 1969 में जब कई माओवादी संगठनों को मिलाकर Communist Party of India (Maoixist -Leninist) का गठन किया गया तो एक वामपंथी अतिवादी संगठन Elite ने अपने को उस विषय से अलग रखा और 1975 में इसने अपना Maoist Communist Centre (MCC) के रूप में किया।

MCC के Airea of Operation के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल बिहार उडीसा झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश है। झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में से 22 जिले नक्सलवाद के परिधि में है एमसीसी के अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के दायरे में नेपाल बंगलादेश एवं श्रीलंका के नक्सलवादी संगठन है। बिहार राज्य के सीमा से सटे नेपाल के माओवादियों से इसके गहरे सम्बन्ध है। जहाँ से इन्हें हथियार एवं प्रशिक्षण प्राप्त होते है साथ ही सदस्यों के आदान प्रदान भी होते हैं।

दूसरे वामपंथी नक्सलवादी संगठन के रूप में Peoples War Group यानि CPI-ML (PW) का नाम लिया जाता है इसका गठन 22 अप्रैल 1980 को Candapalli Sectharamaiah के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में हुआ धीरे–धीरे इसके परिधि में आन्ध्र प्रदेश के अन्य भाग पश्चिम बंगाल उडीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के साथ ही तमिलनाडु केरल कर्नाटक उत्तरप्रदेष हरियाणा पंजाब एवं राजस्थान तक विस्तार हुआ।

भारत में नक्सलवादी हिंसा की वर्तमान स्थिति

नक्सलवादी हिंसा की घटनाएं और उनके परिणाम स्वरूप होने वाली बढ़ती मृत्यु की आवृत्ति देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हे। विगत वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा एवं परिणामगत मृत्यु का ग्राफ अधोलितिखत है–

सारणी संख्या –1

नक्सली हिंसा एवं मृत्यु

सन्	हिंसा	मृत्यु
2001	1,208	564
2003	1,597	515
2005	1,594	669
2008	1591	721
2010	2213	1006
2017	908	203

स्रोत– गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुई नक्सली वारदात में 25 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पिछले 5 सालों में नक्सली हिंसा की 5960 घटनायें हुई थीं। इनमें 1221 नागरिक, 455 सुरक्षाकर्मी और 581 नक्सली मारे गये थे। नोटबन्दी के बाद माना जा रहा है कि नक्सलियों की कमर टूट गयी है लेकिन सुकमा की घटना ने एक बार नक्सली हिंसा को सुलगा दिया है।

दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गृहमंत्रालय से जानकारी मिली है कि साल 2012 में अक्टूबर 2017 तक नक्सली हिंसा के चलते देश में 91 टेलीफोन एक्सचेंज एवं टावर को निशाना बनाया गया। 23 स्कूल भी नक्सलियों के निशाने पर रहे। पिछले 2 वर्षों के अन्दर नक्सल विरोधी अभियान चलाये गये जिसकी वहज से बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

नक्सलियों की बड़ी वारदातें

(1) **6 अप्रैल 2010**–सुकमा में नक्सलियों ने खून की होली खेलते हुए 76 सी0आर0पी0एफ0 के जवानों को मौत के नींद सुला दिया।

(2) **जून 2011**–दन्तेवाड़ा में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट, 10 पुलिसकर्मी शहीद।

(3) **12 मई 2012**–सुकमा में दूरदर्शन केन्द्र पर हमला 4 जवान शहीद।

(4) मई 2013–झीरम में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 32 लोगों को मारा।

(5) **11 मार्च 2014**–टाहकवाड़ा में 20 जवान शहीद।

(6) **30 मार्च 2016**–दन्तेवाड़ा के मालेवाड़ा में 7 जवान षहीद।

(7) **11 मार्च 2017**–भेज्जी में हमला 11 जवान शहीद।

सन् 2010 में हिंसा का ग्राफ बहुत ऊँचा था, इस वर्ष हिंसा की घटनाओं की संख्या 2213 और मृत्यु की संख्या 1005 थी, जबकि 2017 में हिंसात्मक घटनाओं की संख्या अपेक्षाकृत कुछ कम थी।

डॉ. मनोरमा राय

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि 9 राज्यों के 76 जिलों में नक्सली आन्दोलन बुरी तरह से फैल चुका है। इन राज्यों के अन्तर्गत अन्य प्रदेश बिहार मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल अन्तर्विष्ट है गृह मंत्रालय की यह भी सूचना है कि 'पीपुल्स वार ग्रुप' एवं एमसीसीआई संगठन अपने प्रभाव को तमितनाडु कर्नाटक केरल एवं पूर्व प्रभावित राज्यों के अतिरिक्त अन्य नये राज्यों के क्षेत्रों में भी फैलाने का प्रयास कर रहा है।

भारत में नक्सलवाद के कारण

1. **अनधिकृत भौतिक महत्वाकांक्षाओं के अनियंत्रित ज्वार** :– महत्वाकांक्षी होने में कोई दोष नहीं पर बिना श्रम या कम से कम श्रम में अधिकतम लाभ पाने की प्रवृत्ति ही सारी विषमताओं का कारण है।
2. **मौलिक अधिकारों पर हनन का प्रभाव** :– अनियंत्रित महत्वकांक्षाओं के ज्वार में आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर डाका डालने की प्रवृत्ति में असीमित वृद्धि की है नक्सलियों द्वारा जिस वर्ग संघर्ष की बात की जा रही है उसमें समर्थ और असमर्थ ही मुख्य घटक हैं, दलित या आदिवासी जैसे शब्द तो केवल भोले–भाले लोगों को बरगलाने के लिए हैं। समर्थ होने की होड में हर कोई शामिल है।
3. **शोषण की पराकाष्ठायें** :– सामान्यतः आम मनुष्य सहनशील प्रवृत्ति का होता है वह हिंसक तभी होता है जब शोषण की सारी सीमाएं पार हो चुकी होती हैं नक्सलियों के लिए शोषण की पराकाष्ठायें पोषण का काम करती हैं।
4. **सामाजिक विषमता** :– सामाजिक विषमता ही वर्ग संघर्ष की जननी है आजादी के बाद भी इस विषमता में कोई कमी नहीं आयी। नक्सलियों के लिए यह एक बड़ा मानसिक हथियार है।
5. **जनहित की योजनाओं की मृगमारीचिका** :– शासन की जनहित के लिए बनने वाली योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में गम्भीरता निष्ठा व पारदर्शिता का अभाव रहता है जिससे वंचितों को भड़काने और नक्सलियों की नयी पौध तैयार करने के लिए इन माओवादियों को अच्छा बहाना मिल जाता है।
6. **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव** :– आम जनता को यह समझ में आने लगा है कि सत्ताधारियों में न तो सामाजिक विषमताएं समाप्त करने, न भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना बन्द करने और न ही नक्सली समस्या के उन्मूलन के प्रति लेश भी राजनीतिक नक्सलियों को देश में कुछ भी करने का मानसिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी है।
7. **लचीली कानून व्यवस्था, न्याय एवं कडे कानून का अभाव** :– अपराधियों के प्रति कडे कानून का अभाव विलम्ब से प्राप्त होने वाले न्याय से उत्पन्न जन असंतोष एवं हमारी लचीली कानून व्यवस्था ने नक्सलियों के हौसले बुलंद किये हैं।
8. **आजीविकापरक शिक्षा का अभाव एवं महंगी शिक्षा** :– रोजगारोंन्मुखी शिक्षा का अभाव, उपयोग में परिवर्तित होती जा रही शिक्षा के कारण आमजनता के लिए महंगी

और दुलर्भ हुई शिक्षा अनियंत्रित मशीनीकरण, कुटीर उद्योगों के अभाव में आजीविका के दुलर्भ होते जा रहे साधनों से नक्सली बनने की प्रेरणा एवं समस्या का एक बडा नया कारण है।

9. **स्थानीय लोगों में प्रतिकार की असमर्थता :–** निर्धनता, शैक्षणिक पिडछापन, राष्ट्रीयभावना के अभाव, नैतिक उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता और पुलिस संरक्षण के अभाव में स्थानीय लोग नक्सली हिंसाओं का सशक्त विरोध नहीं कर पाते जिसके कारण नक्सली और भी अधिक निरंकुश होते जा रहे हैं।

नक्सलवाद की समस्या का समाधान :–

अधोलिखित उपायों पर ईमानदारी से किये गये प्रयास नक्सलवाद की समस्या के स्थायी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

1. नक्सली समस्या के उन्मूलन के प्रति दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति का विकास क्योंकि बिना दृढ संकल्प के किसी भी उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती।
2. आमनागरिकों के भौतिक अधिकारों की रक्षा के उपायों से विकास के समान अवसरों की उपलब्धता की सुनिश्चितता।
3. शासकीय योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन एवं उनमें पारदर्शिता की सुनिश्चितता जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
4. समुचित एवं सहयोगपूर्ण कानून व्यवस्था जिससे स्थानीय लोग नक्सलियों का प्रतिकार कर सके और उन्हें जीवनोपयोगी आवश्यक चीजें उपलब्ध न कराने के लिए साहस जुटा सकें।
5. कानून व न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल, जिससे लोगों को सहज और समय पर न्याय मिलने की सुनिश्चितता हो सके।
6. आजीविका परक एवं सर्वोपलब्ध शिक्षा की व्यवस्था जिससे सामाजिक विषमता पर अंकुश लग सके।
7. कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के समुचित प्रयास–जिससे वर्गभेद की सीमायें नियंत्रित की जा सके।
8. राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा में नक्सलियों को लाने और उनको पुनर्व्यवस्थापन के लिए रोजगारपरक विशेष पैकेज की व्यवस्था।

नक्सली हिंसा से निपटने के लिए सरकार की रणनीति–

(1) नकसलियों और आधारभूत ढ़ाँचे व सहायक प्रणाली के विरूद्ध एक समन्वित प्रभावी पुलिस कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए सम्मुन्नत सूचना संग्रहण और साझा तन्त्र का निर्माण करना।

(2) नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने सहित त्वरित सामाजिक, आर्थिक विकास के उद्देश्य से जन शिकायतों के प्रभावी निराकरण व समुन्नत

वितरण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का सुदृढ़ीकरण करना तथा उसे अधिक पारदर्शी उत्तरदायी व संवेदनशील बनाना और स्थानीय समूहों को प्रोत्साहित करना जैसे–छत्तीसगढ़ का सलवाजुड़म अभियान।

(3) प्रमाणित राज्यों द्वारा नक्सली गुटों के साथ शान्ति वार्ता करना यदि हिंसा का रास्ता छोड़ने और हथियार त्यागने के लिए तैयार है।

निष्कर्ष

अपने हक को पाने के लिए चलाया गया आन्दोलन नक्सलवाद अब उग्रवाद के रूप में देश के सामने एक अत्यन्त विकट समस्या है, जिसके निराकरण हेतु बहुकोणीय प्रयास की आवश्यकता है। जिसमें नकक्सल प्रभावित इलाका ओर गैर नक्सल प्रभावी इलाका के बीच अन्तर स्पष्ट करते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में अलग से विकास हेतु अल्प मासिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं जिसका समय से कार्यान्वयन पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क, पानी, बिजली, रोजगार के उपलब्धता से सम्बन्धित अवसरों का त्वरित एवं सतत कार्यान्वयन अपेक्षित है। साथ ही नक्सलवाद से प्रभावित मुक्त इलाकों में विकास योजनाओं को समयानुकूल ईमानदारी से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, जिससे नक्सलवाद के प्रभाव में बढ़ोत्तरी को रोका जा सके एवं इसके फैलने की सम्भवना को खत्म किया जा सके। सुशासन, सरकारी तंत्रों तथा नागरिक प्रशासन, खुफिया प्रशासन और स्वयं सेवी संगठनों के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित कर उन क्षेत्रों के लिए बनाये गये योजनाओं का ईमानदारी पूर्वक काय्रान्वयन कर इसे कम किया जा सकता है।

आज सरकार ओर सुरक्षा बलों का नक्सलवाद के प्रति कितना गम्भीर रूख है इससे समझा जा सकता है कि 29 मार्च 2018 को सुकमा में 16 महिला नक्सली समेत 59 नक्सलियों ने पुलिस और सी0आर0पी0एफ0 के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसी क्रम में पिछले दो सालों में सरकार द्वारा 1476 नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाए गये और 1994 गिरफ्तार किये गये लेकिन इस सब के बीच नक्सलियों का आत्मसमर्पण वो उम्मीद की किरण लेकर आया है कि धीरे–धीरे ही सही लेकिन अब इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों का नक्सलवाद से मोह भंग हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ

1. ए0एन0दास, 1983 : *एग्रेरियन अनस्टेट एण्ड सोशियों इकोनामिक चेंज इन बिहार* मनोहर नई दिल्ली, पेज नं0 **112–13**।
2. ए0आर0 नन्दा, ; 1971 : *प्रोविजनल पापुलेशन टोटल्सः रूरल अरबन डिस्ट्री व्यूशन, सेंसर आफ इण्डिया,* 1991 रजिस्टार जनरल आफ इण्डिया, पेज नं0 **67**।
3. डी0आर्चर और पी कॉस्टेलो, 1990 : *लिटरेसी एण्ड पावर,* अर्थस्केन लंदन, पेज नं0 **84–86**।

4. सुमन्त बनर्जी, 1999 (सम्बा) : *श्रीफिंग स्पेशः माइनारटी राइट्स इन साउथ एशिया, नेपाल (ललितपुर) साउथ एशिया फोरन फार हयूमन राइट्स,* पेज नं0 132।

6. बस्तर की अभिव्यक्ति : Blogspot.com 10 फरवरी 2013